भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 39
05 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन

***39. श्री रवनीत सिंह बिट्टू :**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के अंतर्गत आज की तारीख तक सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर पंजाब राज्य में, कुल कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक स्तरों पर मृदा परीक्षण को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास मिट्टी की नियमित जांच सुनिश्चित करने और उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विद्यमान है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन" के संबंध में दिनांक 05.12.2023 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाएं वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। अब, इस योजना का वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत, वर्ष 2014-15 से अब तक पंजाब सहित देश भर में 23.59 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। जहां तक पंजाब की बात है तो राज्य में 26.20 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये हैं। पंजाब सहित, इस योजना के तहत, जारी मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग) सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। इस योजना के तहत स्थैतिक और चल (मोबाइल) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गाँव/ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (वीएलएसटीएल) स्थापित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान हैं। वर्ष 2014-15 से, राज्यों में कुल 8272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (1068 स्थैतिक, 163 चल (मोबाइल), 6376 लघु प्रयोगशालाएँ तथा 665 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएँ) स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि विज्ञानं केंद्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अन्य संस्थानों में भी 1076 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गयीं हैं। इसके अलावा अन्य हितधारकों को शामिल करने और किसान क्षेत्रों के नजदीक ब्लॉक और ग्रांम स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), फार्म उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) आदि द्वारा ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (वीएलएसटीएल) स्थापित की जाती हैं।

(घ) एवं (ड.): सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (https://www.soilhealth.dac.gov.in) के माध्यम से योजना कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है, जिसका वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता है। एक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है जो भौगोलिक सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय मृदा उर्वरता मैप विकसित करने के लिए जियो-टैगिंग कैप्चर करता है। पोर्टल पर सीधे परीक्षण रिपोर्टें अपलोड करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को नया रूप दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों द्वारा सीधे मोबाइल ऐप और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भू-निर्देशांक के साथ पोर्टल पर मैप किया जाता है।

वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में योजना की प्रगति की नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, वास्तविक बैठकों, राज्य दौरों आदि के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल आधारित उर्वरक उपयोगएडवाइजरी राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए) नेटवर्क के माध्यम से किसानों को समय-समय पर जारी की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रदर्शन और उर्वरकों के उचित और एकीकृत उपयोग पर किसानों को प्रशिक्षण इस योजना के अभिन्न अंग हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इन पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी देती है, फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन करती है। मृदा स्वास्थ्य का समाधान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु कृषि स्नातकों के लिए रूरल अवेयरनेस वर्क्स एक्सपीरियंस (आरएडब्ल्यूई) कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है।

वर्ष 2015 से, इस योजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से लगभग 6.45 लाख प्रदर्शन, 93781 किसानों के प्रशिक्षण और 7425 किसान मेले आयोजित की गई हैं।

लो.स.ता.प्र.सं.39

अनुबंध-I

योजना के तहत जारी मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.स.	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	कुल
1	अंडमान और निकोबार	26,397
2	आंध्र प्रदेश	1,46,31,164
3	अरुणाचल प्रदेश	70,273
4	असम	26,64,958
5	बिहार	1,46,69,629
6	छत्तीसगढ	94,71,122
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,57,97
8	गोवा	54,015
9	गुजरात	1,39,32,091
10	हरियाणा	84,15,715
11	हिमाचल प्रदेश	13,71,653
12	जम्मू एवं कश्मीर	21,16,492
13	लद्दाख	1,718
14	झारखंड	9,25,359
15	कर्नाटक	1,70,18,659
16	केरल	33,26,999
17	मध्य प्रदेश	1,82,44,638
18	महाराष्ट्र	2,64,57,060
19	मणिपुर	2,56,864
20	मेघालय	4,37,946
21	मिजोरम	30,616
22	नागालैण्ड	2,27,988
23	ओडिशा	52,00,023
24	पुदुचेरी	34,255
25	पंजाब	**26,19,539**
26	राजस्थान	1,92,57,558
27	सिक्किम	1,15,085
28	तमिलनाडु	1,41,68,507
29	तेलंगाना	1,08,39,437
30	त्रिपुरा	3,20,558
31	उत्तर प्रदेश	3,77,25,218
32	उत्तराखंड	16,79,779
33	पश्चिम बंगाल	95,54,921
कुल		**23,58,82,033**

******